सनातन पुरातन और नूतन की अवधारणा पर सजेगा सिंहस्थ

- कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को दिए टिप्स
- पुरातन वैभव और आधुनिक विकास बनेगा सिंहस्थ की पहचान
- सिर्फ रील नहीं, उज्जैन को लाभ देने वाले कंटेंट की जरूरत

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ-2028 को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है. कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने शहर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक लेकर उन्हें सनातन पुरातन और नूतन की अवधारणा के साथ उज्जैन की पहचान दुनिया तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया.

कलेक्टर ने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ में 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु, साधु-संत और अतिथि आएंगे. ऐसे में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम न होकर, शहर की आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति का माध्यम बने.

कंटेंट ऐसा हो श्रद्धालु रुके-कलेक्टर ने कहा कि कंटेंट ऐसा हो, जिससे आने वाले अतिथि यहां कम से कम 2 से 4 दिन रुकें, जिससे स्थानीय व्यापार और सेवाओं को लाभ मिले. उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल रील या वीडियो बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उज्जैन, सिंहस्थ और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के हित में उपयोगी सिद्ध हो और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए.

सनातन क्या है ,दिखाओ-बैठक में कलेक्टर ने सोशल मीडिया पर उज्जैन का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि शहर में धर्म, दर्शन और अध्यात्म की झलक स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए. उज्जैन केवल महाकाल तक सीमित नहीं, बल्कि यहां 84 महादेव, सप्तसागर, रुद्रसागर, प्राचीन देवालयों का विशाल इतिहास है. इनका महत्व, परंपरा और आध्यात्मिक धरोहर दुनिया तक पहुंचे.

नूतन उज्जैन की परिकल्पना-इसके साथ ही नूतन उज्जैन यानी शहर में तेजी से हो रहे विकास कार्य भी सोशल मीडिया पर प्रमुखता से दर्शाए जाएं. सिंहस्थ से पहले शहर में सड़कों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, ब्रिज निर्माण, रोपवे, आईटी पार्क, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्ट विस्तार, मेडिसिटी, औद्योगिक निवेश जैसे कार्य एक आधुनिक उज्जैन की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं. कलेक्टर ने कहा कि यह संयोजन बताएगा कि उज्जैन केवल पुरातन संस्कृति का प्रहरी ही नहीं, बल्कि नए भारत के आधुनिक विकास का ध्वजवाहक भी है.

अच्छा कंटेंट बनाया तो मिलेगी सुविधा

इन्फ्लुएंसर्स ने बैठक में कई बार मंदिर परिसर और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर प्रवेश न मिल पाने की समस्या भी रखी. इस पर कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि यदि आप गुणवत्तापूर्ण और शहर को लाभ पहुँचाने वाला कंटेंट बनाते हैं, तो प्रशासन स्वयं आवश्यक पहचान-पत्र जारी करेगा. 28 लाख फॉलोअर्स वाले उज्जैन लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालक नितिन शर्मा ने भी अपने सुझाव देते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन हमें कंटेंट फोटो वीडियो उपलब्ध कराएगा तो और आसानी होगी, कलेक्टर ने पॉइंट नोट किया.

शहर की छवि को नुकसान न पहुंचे-दर्जनो ऐसे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है शहर में है जो केवल व्यूज़, सब्सक्राइबर या प्रसिद्धि पाने के लालच में ऐसा कंटेंट न बनाया जाए जो शहर की छवि को नुकसान पहुंचाए. इधर कलेक्टर ने साफ कहा कि सोशल मीडिया पर उज्जैन को लेकर गंभीरता और संवेदनशीलता हो. क्या पोस्ट करना है, कब करना है और उसका क्या असर पड़ेगा, इसका जिम्मेदारी से विचार जरूरी है. प्रशासन उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ खड़ा होगा जो उज्जैन की छवि मजबूत करें, न कि क्षति पहुंचाने वाले कंटेंट के पीछे जाएं.

सुशासन दिवस के शपथ समारोह में उपस्थित रहेंगे सभी अधिकारी

भोपाल, 10 दिसंबर. मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में 24 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे सुशासन दिवस की शपथ दिलाई जायेगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, अवर सचिव विन्ध्यांचल एवं सतपुड़ा भवन सहित मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिये हैं. उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदण्डों के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उनके जन्म दिवस 25 दिसम्बर के एक दिन पूर्व 24 दिसम्बर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है.

प्रदेश में अगले दो दिनों तक कड़ाके की ठंड

25 शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

भोपाल,10 दिसंबर. मध्य प्रदेश इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है. उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं, ऊपरी हवा में सक्रिय जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के संयुक्त प्रभाव से तापमान तेजी से गिर रहा है.

मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए भी भोपाल, इंदौर, विदिशा, राजगढ़, शाजापुर और सीहोर जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में कई शहरों में तापमान लगातार गिर रहा है. शहडोल के कल्याणपुर में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा. भोपाल में रात का तापमान 7.2 डिग्री, जबकि इंदौर सहित 25 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया.

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दिसंबर और जनवरी में लंबे समय तक ठंड का यह सिलसिला जारी रह सकता है. पिछले 24 घंटों में प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहा. भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, शाजापुर और शहडोल जिलों में शीतलहर ने असर दिखाया.

इंदौर में 5 .4 डिग्री पहुंचा तापमान

इंदौर जिले में तीव्र शीतलहर दर्ज की गई, तापमान 5 .4 डिग्री पहुंचा. अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इंदौर संभाग में यह सामान्य से 2 डिग्री तक कम रहा. न्यूनतम तापमान भी कई संभागों में सामान्य से नीचे रहा.

जल जीवन मिशन जल्द पूरा करेगा मध्यप्रदेश

सीएम डॉ. यादव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिया टॉस्क

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 दिसंबर. जल जीवन मिशन के काम में पीछे चल रहे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्र सरकार की डेडलाइन से 21 माह पहले काम पूरा करने का टॉस्क दिया है.

केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के काम को पूरा का लक्ष्य संशोधित कर इसे दिसंबर 2028 कर दिया है, लेकिन मप्र में ये काम अब मार्च 2027 तक पूरा करना होगा. उन्होंने कहा है कि इस मामले में मप्र को राष्ट्रीय स्तर पर मिशाल पेश करना है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बुधवार को मंत्रालय में पीएचई विभाग की दो वर्ष की उपलब्धि और तीन वर्ष की कार्ययोजना को लेकर बैठक की. ये बैठक मंगलवार को ही खजुराहो में होनी थी, लेकिन समय की कमी के कारण नहीं हो सकी, ऐसे में अब मंत्रालय में हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी स्थिति में जल स्त्रोतों में सीवरेज का दूषित जल नहीं मिले और इसके लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह भी कहा कि जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों और महिला समूहों को राज्य, संभाग, जिला और ग्राम स्तर पर सम्मानित किया जाए.

विगत 10 वर्षों में जिन ग्रामों को जल संकट का सामना करना पड़ा है, उनकी रिपोर्ट तैयार कर उन क्षेत्रों में जल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जल की उपलब्धता के अनुसार जल वितरण का समय तय किया जाए, जिससे नियमित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके. मिशन के प्रभाव का विश्लेषण अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से कराए जाने की बात भी कही. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गांव के ऐसे ट्यूबवेल की सूची बनवाएं, जिनमें हमेशा पानी रहता हो और ट्यूबवेल मालिक सेवाभावी हों. जरूरत पड़ने पर इनके ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति कराने का प्रयास करें.

बैठक में भविष्य के विजन पर जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी तीन वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर तक सुरक्षित नल-जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

80 लाख घरों में पहुंचा नल-जल कनेक्शन

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पी. नरहरि ने बताया कि अब तक प्रदेश में 80 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं और मिशन की कुल प्रगति 72 .54 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में 8 .19 लाख कनेक्शन का लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा किया गया है और वर्ष 2025-26 में अब तक 5 .50 लाख कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं. बैठक में बताया गया कि मप्र बोरवेल दुर्घटना रोकने के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है. साथ ही स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान में प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान मिला है. प्रदेश में 21,552 ग्राम हर घर जल घोषित किए जा चुके हैं तथा 15,026 ग्रामों को प्रमाणित किया जा चुका है.

जहरीले कचरे की राख के मामले में कोर्ट की रोक

रासायनिक कचरा की राख आबादी वाले क्षेत्र के पास नष्ट करने का मामला

जबलपुर, 10 दिसंबर. हाईकोर्ट ने यूनियन कार्बाइड(यू.सी.)के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण से निकली राख के विनष्टीकरण आबादी वाले क्षेत्र से सिर्फ पांच सौ मीटर दूर किये जाने पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट के इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार की तरफ से आवेदन पेश किया गया है.

हाईकोर्ट जस्टिस विवेक कुमार सिंह तथा जस्टिस अजय कुमार निरंकारी की युगलपीठ ने आवेदन पर दो सप्ताह बाद सुनवाई निर्धारित की है. साल 2004 में आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रही थी. पूर्व में हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने 8 अक्टूबर 2025 को जारी अपने आदेश में कहा था कि जहरीले कचरे की राख की लैंडफिलिंग के लिए आदेश के बावजूद भी सरकार के द्वारा दूसरे स्थान के संबंध में जानकारी नहीं दी गई.

युगलपीठ ने राज्य सरकार को किया था निर्देशित

कचरा ज़हरीला है और इसे ठीक से नहीं रोका गया तो भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसे रोकने वाला स्ट्रक्चर ही टूट जाए या गिर जाए, तो एक और आपदा होगी। सरकार को ज़हरीली राख को ऐसी जगहों पर ले जाने की संभावना पर विचार करना चाहिये जो इंसानी बस्तियों, पेड़-पौधों और पानी के सोर्स से बहुत दूर हों। कंटेनमेंट सिस्टम टूट भी जाए, तो भी इसके बुरे असर बहुत कम हों। युगलपीठ ने राज्य सरकार को निर्देशित किया था कि जहरीले कचरे की राख की लैंडफिलिंग की सबसे अच्छी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ पाने के लिए कोई ग्लोबल टेंडर निकाला जाए, जिनके पास इस तरह का काम करने और ज़हरीले केमिकल कचरे को कंटेन करने के अनुभव हो, इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत करें।

इंदौर में कुर्सी पर बैठे-बैठे युवक की मौत

दुकान में काम करते समय अचानक गिरा

नव भारत न्यूज

इंदौर, 10 दिसंबर.भंवरकुआं थाना क्षेत्र की एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मंगलवार दोपहर अचानक हुए हादसे ने सभी को चौंका दिया.

मोबाइल फाइनेंस का काम कर रहे एक युवक की दुकान में ही तबीयत बिगड़ी और वह कुर्सी से नीचे गिर पड़ा. हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना का वीडियो बुधवार को सामने आया, जिसके बाद मामला चर्चा में आया. थाना प्रभारी राजकुमार यादव ने बताया कि 31 वर्षीय मृतक शिवनारायण मालवीय मूसाखेड़ी में रहता था और तीन ईमली क्षेत्र स्थित अजय इंटरप्राइजेस में निजी फाइनेंस कंपनी की ओर से काम करता था. बताया गया कि वह एक ग्राहक की

फाइनेंस प्रक्रिया पूरी कर रहा था, तभी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा. परिजन ने पुलिस को बताया कि शिवनारायण सुबह बिल्कुल सामान्य था और रोज की तरह ही घर से निकला था. दोपहर में दुकान के एक कर्मचारी ने फोन कर चक्कर आने के बाद गिरने की जानकारी दी. मामले में परिजनों का कहना है कि प्रारंभिक रूप से साइलेंट अटैक का संदेह हो सकता है, हालांकि पुख्ता कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा. चूंकि परिवार मूल रूप से कन्नौद तहसील के महुरिया गांव का रहने वाला है, इसलिए उनका अंतिम संस्कार वहीं किया जाएगा.

कांग्रेस की तथ्य अन्वेषण समिति को रोका

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 दिसंबर. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तथ्य अन्वेषण समिति को बुधवार को सिंगरौली स्थित बेरदहा कोल ब्लॉक पहुँचने से स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन ने रोक दिया.

यह वही क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई, भूमि अधिग्रहण विवाद, गंभीर प्रदूषण और आदिवासी विस्थापन के आरोप लगे हुए हैं. समिति ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रभावित ग्रामीणों से मिलने या वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने तक की अनुमति नहीं दी गई, जिसे उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया.

समिति में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कांग्रेस कार्यसमिति सदस्य कमलेश्वर पटेल और ओंकार मरकाम, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व उपसभापति हीना कावरे, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, तथा पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और बाला बच्चन सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल थे।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 किसानों की मौत

भिंड. जिले के लहार अनुभाग के नानपुरा गांव के पास टूटी पुलिया से एक ट्रैक्टर नहर में जा गिरा, जिससे उसमें सवार तीन किसानों की मौत हो गई. कल देर रात हुए इस हादसे की आज तड़के जानकारी मिली, जब तीनों के शव ट्रॉली के नीचे दबे पाए गए. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकलवाया और लहार अस्पताल भिजवाया. मृतकों की पहचान रावतपुरा सानी गांव निवासी झींगुरी सिंह राजपूत, बलवीर सिंह राजपूत और शिवेंद्र सिंह राजपूत के रूप में हुई है. तीनों धान बेचने के लिए उत्तरप्रदेश गए थे और कल देर रात वापस लौट रहे थे. हादसा अंधेरे में हुआ, इसलिए किसी को तुरंत इसकी जानकारी नहीं मिल पाई.

योजनाओं को प्रभावी बनाने फीडबैक जरूरी

कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 10 दिसंबर. स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी जनसमस्याओं का समाधान किया.

जिन जनसमस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो सका, उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया. कार्यकर्ताओं से संवाद एवं समन्वय के बाद मंत्री ने कहा कि प्रदेश कार्यालय में शुरू की गई कार्यकर्ताओं से संवाद की व्यवस्था मंत्रियों को कार्यकर्ताओं व जनता से सीधे जुड़ने का अवसर दे रही है. कार्यकर्ताओं से मिलने वाला फीडबैक भाजपा सरकार योजनाओं को और प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा. राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को अब जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश शासन के मंत्रियों के बंगले या वल्लभ भवन जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ही मंत्रियों द्वारा किए जाने वाले संवाद में जनसमस्याओं का समाधान हो रहा है. आज मैंने भी प्रदेश कार्यालय में अनेक कार्यकर्ताओं व वरिष्ठजनों से संवाद कर उनकी जनसमस्याएं सुनीं और समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं.

कार्यकर्ताओं से मुलाकात व संवाद के दौरान सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं पर मूल्यवान फीडबैक प्राप्त हो रहा है, जो सरकार की योजनाओं को और प्रभावी बनाने में सहायक होगा. यह व्यवस्था पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ आम जनता के लिए भी सुविधा बढ़ाने वाली है, जिससे समय, ऊर्जा और संसाधनों की बचत हो रही है. आने वाले समय में यह पहल सरकार, संगठन और जनता के बीच सेतु का मजबूत एवं लाभकारी माध्यम बनेगी.

आरोप: ट्रांसप्लांट किए गए 90 प्रतिशत से अधिक पेड़ या तो जीवित नहीं रहे या बाद में चुपचाप हटाए गए

अनियोजित शहरी परियोजनाओं पर कांग्रेस चिंतित

विशेष संवाददाता

भोपाल, 10 दिसंबर. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित राज्य के प्रमुख शहरों में अनियोजित और बिना दूरदृष्टि वाली शहरी परियोजनाओं के तेजी से बढ़ते विस्तार पर गंभीर आपत्ति जताई है.

पार्टी का आरोप है कि सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर निर्माण और मेट्रो परियोजनाओं जैसी व्यापक योजनाओं को जनहित के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि इनका वास्तविक लाभ प्रभावशाली ठेकेदारों और राजनीतिक हितधारकों को मिल रहा है. कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया के अनुसार इन परियोजनाओं का सबसे भयावह प्रभाव शहरी हरियाली का तेजी से खत्म होना है. पिछले कुछ वर्षों में लाखों पेड़ों की कटाई हुई है, जबकि ट्रांसप्लांटेशन के नाम पर किए गए प्रयास सिर्फ दिखावा भर साबित हुए हैं.

कांग्रेस नेताओं का दावा है कि ट्रांसप्लांट किए गए 90 प्रतिशत से अधिक पेड़ या तो जीवित नहीं रहे या बाद में चुपचाप हटा दिए गए, जिससे शहरों में हरित आवरण में भारी गिरावट आई है. परिणामस्वरूप, भोपाल सहित अन्य शहरों में वायु गुणवत्ता

सूचकांक तेजी से बिगड़ रहा है और आने वाले महीनों में इसके और खराब होने की आशंका है.

कांग्रेस का कहना है कि महंगी मेट्रो रेल परियोजनाएं केवल उन महानगरों के लिए उपयुक्त होती हैं, जहां जनसंख्या घनत्व 50,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो. इसके साथ ही मजबूत आईटी कॉरिडोर और दैनिक यात्री संख्या लाखों में हो. इसके विपरीत, भोपाल जहां घनत्व मात्र 8,000-10,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इंदौर इस मानक पर खरे नहीं उतरते. पार्टी का तर्क है कि मेट्रो न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाएगी बल्कि ट्रैफिक अव्यवस्था को भी बढ़ाएगी, जैसा कि पहले की बीआरटीएस परियोजना में देखा गया था.

कांग्रेस ने सभी मेट्रो परियोजनाओं पर तत्काल रोक, निष्पक्ष तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन और सड़क व फ्लाईओवर कार्यों के लिए पेड़ कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है. यदि कटाई अपरिहार्य हो, तो प्रति पेड़ दस नए पौधे लगाने और पांच वर्ष का रख-रखाव सुनिश्चित करने की शर्त अनिवार्य करने पर जोर दिया है. इसके साथ ही पार्टी ने कम लागत वाले, पर्यावरण-अनुकूल परिवहन विकल्पों बेहतर बस नेटवर्क, साइकिल ट्रैक, पैदल मार्ग और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने तथा वर्तमान शहरी परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

पेज एक के शेष

एमपी सरकार अपने खर्च पर बनाएगी हाई-स्पीड कॉरिडोर

मिलेगा. तीन वर्ष की कार्ययोजना के दौरान बताया गया कि सड़क सुरक्षा पर केंद्रित रोडसाइड एमेनिटीज, ब्लैकस्पॉट सुधार और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा. जीआईएस आधारित रोड मास्टर प्लान को पूर्ण रूप से लागू कर भविष्य की सड़क परियोजनाओं का चयन वैज्ञानिक विश्लेषण, यात्रा दूरी, औद्योगिक आवश्यकताओं और यातायात घनत्व के आधार पर किया जाएगा. तीन वर्ष के रोडमैप के मुताबिक निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को और सख्त किया जाएगा, जिसमें मोबाइल लैब, त्वरित परीक्षण, ह्व आधारित रिपोर्टिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग शामिल होगी. शहरी क्षेत्रों में नए आरओबी, फ्लाईओवर, बायपास और स्मार्ट कॉरिडोर विकसित कर शहरों के ट्रैफिक प्रेशर को कम करने और कम्यूटिंग समय घटाने का लक्ष्य निर्धारित है. वहीं अगले तीन वर्षों में पूरी विभागीय एसेट इन्वेंटरी को 100 फीसदी डिजिटल, जियो-रेफरेंस्ड और ऑटो-अपडेटिंग सिस्टम में परिवर्तित किया जाएगा, जिससे योजना, बजट निर्धारण और फील्ड मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी होगी.

बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया और समीपवर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ायें. पूरे प्रदेश को समावेशित कर समग्र विकास पर कार्य करें.

शाह के तीखे प्रहार

- विपक्ष चार महीने से झूठ फैला रहा है
- विपक्ष जहां जीतता है वहां वोटर लिस्ट अच्छी है और जहां हारता है वहां लिस्ट गलत हैं
- कुछ लोग पुश्तैनी वोट चोर है
- आय की मुंसफी से संसद नहीं चलेगी
- 73 वर्षों तक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं था
- विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट की भी बात नहीं मानते.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60